tails as called for in the question are not available. Any cases of hardships of employees in a Regional Rural Bank can be looked into by Government NABARD and the concerned RRB.

Pay scales of Field Supervisors in R.R.Bs. Functioning in Uttar Pradesh

4213. SHRI ASHIS SEN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a few Regional Rural Banks in Uttar Pradesh have allowed the revised pay scales of Uttar Pradesh Government to their Field Supervisors as per Government orders dated the 29th April, 1990;

(b) if so, what are the names of these Banks; and

(c) what are the reasons for the rest of the RRB's in the State not adhering to these orders?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (c). National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) has reported that they are not aware of any order dated 29-4-90 by Government of Uttar Pradesh. The then Field Supervisors of Regional Rural Banks (RRB's) were equated with Assistant Development Officers of Uttar Pradesh Government and the RRBs in the State were required to maintain that parity. Now, the cadre of Field Supervisors stands abolished. The details as called for in the question are not available. Any cases of hardships of employees in any RRB can be looked into by Government, NABARD and the concerned RRB.

Selection of Field Supervisors in R.R.B's

4214. SHRI ASHIS SEN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have instructed the Regional Rural Banks not to go ahead with the recruitment of Field Supervisors selected and sponsored by the BSRB;

(b) what is the number of such Field Supervisors selected; and

(c) what are the reasons for the above instructions of Government and what will be the fate of those selected and not recruited?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (c). Government had issued instructions on 22-2-91 to all the Regional Rural Banks (RRBs) in pursuance or acceptance of the award of the National Industrial Tribunal (NIT) and the recommendations of Equation Committee granting sponsor bank pay scales and other benefits to RRB staff with effect from 1-9-87. With the implementation of the NIT award, the post of Field Supervisor existing in the RRBs stands abolished and equated with the post of JMG Scale I of Public Sector Banks. National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) had advised all the Banking Service Recruitment Boards in October, 1991 that no recruitment can be made to the post of Field Supervisorin RRBs and the indents, if any placed by RRBs for these post may be treated as cancelled.

मोदी उद्योग समूह पर आयकर तथा उत्पाद शुल्क की बकाया राशि

4215. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार मोदी उद्योग समूह पर आयकर और उत्पाद शुल्क की कितनी रकम बकाया थी ; और

(ख) सरकार द्वारा इस बकाया रकम की वसूली के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क)

आयकर :

कारबार समूह-वार सूचना नहीं रखी जाती है। तथापि, इस समूह की छह कंपनियों के संबंध में सूचना उपलब्ध है, जो संलग्न विवरण में दी गई है। (नीचे देखिए)

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क :

सूचना समूह-वार नहीं रखी जाती है क्योंकि क्षेत्रीय कार्यालयों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यहां तक कि उद्गम स्तर पर भी प्रत्येक अधिकारी को यह मालूम नहीं होता है कि शुल्क अदा करने वाली कौन सी इकाई किस समूह से संबंधित हैं। इस प्रकार, वांछित सूचना को प्रस्तुत कर पाना संभव नहीं है।

(ख)

आयकर :

सरकार द्वारा बकाया धनराशि को वसूल करने के निमित्त की गई कार्य वाहियों को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। (नीचे देखिए)

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क :

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की बकाया राशि को वसूल करने के लिए प्रशासनिक विधायी तथा अन्य उपाय, जो आवश्यक समझा जाए, निरन्तर रूप से किए जा रहे हैं।

विवरण

दिनांक 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार आयकर की बकाया मांग का विवरण-पत्र

क्र० सं०	नाम	दिनांक 31 मार्च, 92 की स्थिति के अनुसार बकाया मांग (करोड़ रु० में)	वसूली के लिए किए गए उपाय
2		3	4
1.	मोदी रबड़ लि०	28.40	इस मांग में से कर-निर्धारण वर्ष 1988–89 से संबंधित 13.48 करोड़ रु० की वसूली आयकर अपील अधिकरण द्वारा स्थापित कर दी गई है। कर-निर्धारण वर्ष 1989–90 से संबंधित 7.20 करोड रु० की मांग अपीलीय प्रभाव के पश्चात् घटकर "शून्य" रह गई है। शेष मांग के लिए 50 लाख रु० प्रति माह की किस्त निश्चित की गई है। इसके परिणामस्वरूप अब तक 1.00 करोड़ रु० की वसूली कर ली गई है।

1	2	3	4
2.	मोदी पांन लि०.	30.60	वसूली के विविध उपायों के परिणामस्वरूप यह बकाया मांग घटकर 22.86 करोड़ रु० रह गई है । कर-निर्धारिती को निम्नानुसार किस्तों की मंजूरी दी गई है :— 35.00 लाख रु०दि—सम्बर 1992 एक-एक करोड़ रु०—जनवरी, फरवरी तथा मार्च, 1993 में ।
3.	मोदी इण्डस्ट्रीज लि०	4.43	वसूली के विविध उपायों के परिणाम स्वरूप यह मांग घटकर 73.20 लाख रु. रह गई है । अपीलय प्रभावों के पश्चात् शेष मांग की वसूली के लिए सभी प्रशासनिक तथा विधायी उपाय किए जायेंगे ।
4.	मोदी ओ ड्स लि०	3.25	वसूली के विविध उपायों के परिणाम स्वरूप अब यह मांग घटकर 19.79 लाख रु० रह गई है । इसकी वसूली के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं ।
5.	मोदी कारपेट्स लि०]	0.37	इस मांग की वसूली के लिए धारा 221 के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ की की गई है ।
6.	मोदी नगर चेरिटेबल सोसाईटी लि०	0.73	समूची मांग में अब घटौती/उसकी वसूली कर ली गई है ।

Conversion of IFCI into a Company

4216. SHRI ASHIS SEN: Will the Minister of FINANCE be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 150 given in the Rajya Sabha on the 24th November, 1992 and state:

(a) what are the reasons for converting Industrial Finance Corporation of India into a company under the Companies Act;

(b) what is the envisaged share holding structure for its conversion into a company; and

(c) what would be the authority monitoring and supervising its functions and operations after such conversion?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) Continued decline in tht availablity of concessional funds from the Government and the Reserve Bank of India (RBI) over the years as also the changes in the past several months in the financial sector have made it obligatory for the Industrial Finance Corporation of India (IFCI) to raise resources largely from the market. However, the IFC Act, 1948 permits IFCI